

an&gt;

Title: Regarding uniformity in Minimum Wages.

**श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद):** अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात सदन में रखना चाहता हूँ जो समाज का सबसे कमजोर कर्मचारी है, मजदूर है, उसे दो प्रकार का न्यूनतम वेतन मिलता है। एक राज्य सरकार तय करती है और एक केंद्र सरकार तय करती है। विभिन्न राज्यों में अगर आप देखें तो उनकी न्यूनतम मजदूरी, केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है, उसकी आधी भी नहीं है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि राज्य सरकारों से समन्वय कर के न्यूनतम मजदूरी को या तो एक करें या बहुत ज्यादा जो गैप है, कहीं दुगने का गैप है, उस गैप की पूर्ति करें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करोड़ों गरीबों का उद्धार किया है। मैं समझता हूँ कि इस बिंदु पर न्यूनतम मजदूरी के मामले में भी इनका उद्धार करने का काम करें। आपके माध्यम से मेरी यही विनती है।

धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:**

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं

श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।